IJMRSETM

e-ISSN: 2395 - 7639

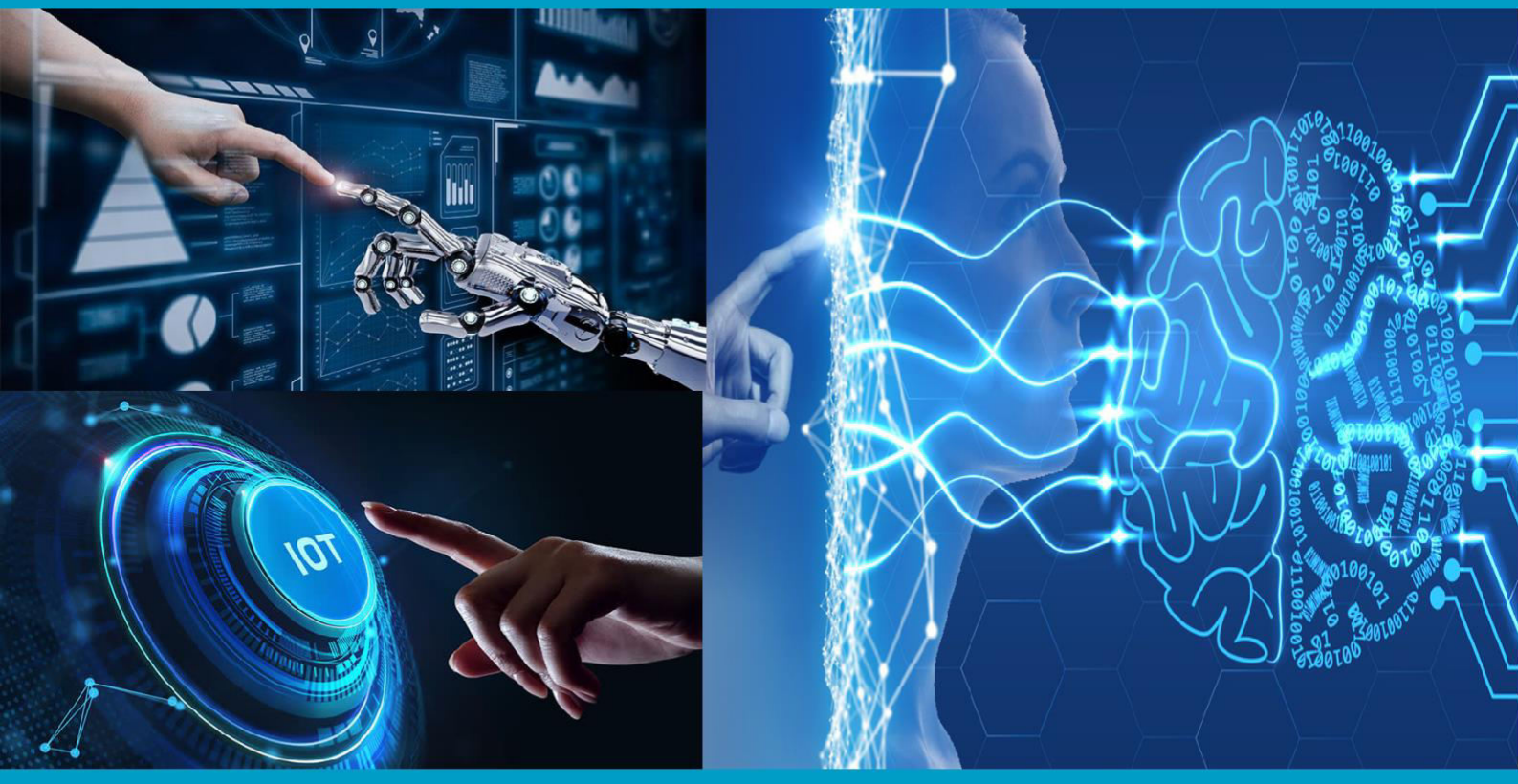

INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH

IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

Volume 10, Issue 8, August 2023

INTERNATIONAL STANDARD SERIAL NUMBER INDIA

Impact Factor: 7.580

International Journal of Multidisciplinary Research in Science, Engineering, Technology & Management (IJMRSETM)

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

राजस्थान विधान सभा चुनाव में महिला की भूमिका

Gaurav Choudhary

Assistant Professor, Political Science, Government College, Jahazpur, Bhilwara, Rajasthan, India

सार

राजस्थान विधानसभा चुनाव में महिला उम्मीद्वारों ने जीत हासिल कर सबको सलाम करने पर मजबूर कर दिया। विजय रथ पर सवार ये 26 महिलाएं आज उन लोगों में शामिल हैं जो सत्ता के गलियारे में दिखाई पड़ते हैं।

राजस्थान विधानसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाली महिला विधायकों में 21 भाजपा की। कांग्रेस की महज एक महिला उम्मीदवार शंकुतला रावत ही चुनाव जीत पाई। इनके अलावा राजपा की गोलमा देवी और गीता वर्मा ने जीत हासिल किया। बस्सी सीट से अंजू देवी ने निर्दलीय उम्मीद्वार के तौर पर जीत दर्ज की।

राजस्थान की प्रथम विधानसभा के आम चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जीरो था। यानी एक भी महिला पहले चुनाव में निर्वाचित होकर विधानसभा नहीं पहुंची। अब 14वीं विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी शून्य से साढ़े तेरह प्रतिशत तक बढ़ गई है। यह देशभर की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है।

परिचय

राजस्थान में 2013 के विधानसभा चुनाव में कुल 92 प्रतिशत पुरुष (कुल पुरुष उम्मीदवार 1930) और 8 प्रतिशत महिला (कुल महिला उम्मीदवार 166) उम्मीदवार मैदान में थे. लेकिन जब चुनाव नतीजे आए तो 86 फीसदी सीटों पर ही पुरुष उम्मीदवार जीते, जबकि महिला उम्मीदवारों ने 14 फीसदी सीटों पर जीत का डंका बजा डाला. जीत का दंभ भरने वाले कई पुरुष राजनेताओं को इन महिला उम्मीदवारों ने ऐसी धूल चटाई कि कइयों की जमानत जब्त हो गई.[1]

यही कारण है कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी अपनी हर सभा में महिला नेत्रियों और उम्मीदवारों को ज्यादा से ज्यादा तवज्जो देने की बात कह रहे हैं. वहीं, बीजेपी भी इसमे पीछे नहीं है. बीजेपी की जबरदस्त जीत में तो इन महिलाओं ने ऐसा कमाल किया कि 'मरुधरा में वसुंधरा' की जय जयकार करवा दी. तब चुनाव में बीजेपी ने 26 यानी 13 प्रतिशत टिकट महिला उम्मीवारों को दिए थे, जिनमें से 22 महिला उम्मीदवारों ने विजयी पताका फहराया. यानी उनकी जीत की परफॉर्मेंस 84.6 फीसदी रहा. जबकि बीजेपी ने पुरुष उम्मीदवारों को 174 यानी 87 फीसदी टिकट दिए और उनकी जीत की परफॉर्मेंस महिलाओं की तुलना में कम यानी 81 फीसदी ही रही.

2013 विधासनभा चुनावों के बाद जहां 172 पुरुष उम्मीदवार सदन में पहुंचे तो दूसरी ओर कम सीटों पर चुनाव लड़ने के बावजूद पुरुषों से ज्यादा जीत का औसत लेकर 28 महिला उम्मीदवार विधानसभा तक पहुंची. ऐसे में टिकट वितरण से पहले कांग्रेस, बीजेपी के राजनीतिक क्षत्रप ज्यादा से ज्यादा जीताऊ महिला उम्मीदवारों पर दांव लगाने की तैयारी में हैं, टिकट वितरण, मेनिफेस्टों से लेकर मतदान तक महिलाओं पर फोकस है. हालांकि इस बार भी पुरुषों की तुलना में आधी से भी कम महिला उम्मीदवारों को बीजेपी, कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टियां मैदान में उतारेंगी, इसमें कोई दो राय नहीं.

2013 के चुनावों में शहरी क्षेत्रों में जहां पुरुष मतदान प्रतिशत 72.35 था, वहीं महिलाओं का वोट प्रतिशत 71.73 प्रतिशत रहा. यानी एक प्रतिशत से भी कम अंतर रहा. जबकि राजस्थान के गांवों में 75.66 प्रतिशत पुरुषों और 76.66 प्रतिशत महिला मतदाताओं ने ही अपने मताधिकार का प्रयोग किया, यानि महिलाओं ने पुरुषों से ज्यादा वोट डाले. यही सब कारण है कि दोनों ही बड़े राजनीतिक दलों के साथ अन्य पार्टियां भी महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर अपने मेनिफेस्टो और टिकट वितरण में फोकस में जुटी हैं. ताकि महिलाओं के ज्यादा से ज्यादा वोट अपने खाते में डलवाए जा सकें.

भारत के इतिहास में आधुनिक काल राजनीति में महिलाओं की भागीदारी से अधिक महत्वपूर्ण है। रानी लक्ष्मीबाई, मैडम बीकाजी कामा, कस्तूरबा, अरुणा आसफ अली, सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी,

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

विजयलक्ष्मी पंडित, इंदिरा गांधी आदि ने हमारे स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वाधीनता की राजनीति में नंदिनी सत्पथी, मोहसिना किदवई, गिरिजा व्यास, सुषमा स्वराज, मायावती, वसुंधरा राजे, शीला दीक्षित, ममता बनर्जी, रेणुका चैधरी, सोनिया गांधी आदि ने सक्रियता दिखाई। इंदिरा गांधी ने 16 वर्षों तक प्रधानमंत्री के रूप में देश का नेतृत्व किया। स्वतंत्रता के तुरंत बाद गठित देश के संविधान में, महिलाओं को न केवल पुरुषों के रूप में वोट देने के लिए समान अधिकार दिए गए हैं, बल्कि पंचायत से संसद तक जनता का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुनाव भी लड़ना है।[2]

इस प्रकार पंचायत राज व्यवस्था में सभी जनप्रतिनिधि मंचों में कम से कम एक तिहाई सदस्यता के साथ राजनीति में महिला भागीदारी का संख्यात्मक प्रतिनिधित्व बढ़ा है। महिलाओं के लिए सार्वजनिक प्रतिनिधित्व कानून द्वारा एक तिहाई सदस्यता के प्रतिनिधित्व के कारण समाज में पुरुषों और महिलाओं के समानता का विचार तेजी से बदल रहा है। महिलाओं में नया आत्मविश्वास पैदा हुआ है। खुद के प्रति उनकी छवि में सुधार हुआ है, वे अपनी आँखों में उग आए हैं। समाज में महिलाओं से संबंधित मुद्दों पर विशेष जोर दिया गया है, महिलाओं के खिलाफ अत्याचार, बल का उपयोग आदि के विरोध में जागरूकता बढ़ी है, बालिका शिक्षा को बढ़ावा दिया गया है। [3] महिला मतदाताओं का सम्मान बढ़ा है, लेकिन विडंबना यह है कि संसद और विधानसभाओं में एक तिहाई महिला भागीदारी बढ़ाने का विधेयक 1998 से लंबित है, जो पुरुष - प्रधान समाज के अन्यायपूर्ण फैसले का कड़वा मामला है।

विचार-विमर्श

महिला आरक्षण का मुद्दा राजनीतिक गलियारों में गाहे बगाहे उठता रहता है। लेकिन महिलाओं को विभिन्न राजनीतिक पार्टियों ने अभी तक उस संख्या में प्रत्याशी नहीं बनाया जितने की वकालत उनके नेता करते हैं। राजस्थान में अगर जीत के प्रतिशत के आंकड़ों पर गौर करें तो जीतने वालों में महिला प्रत्याशी पुरुष प्रत्याशियों से कहीं आगे हैं। राजस्थान देश का पहला राज्य था जहां महिलाओं को पंचायत और नगरपालिका चुनाव में 50 प्रतिशत आरक्षण दिया गया। यह आरक्षण 2008 में भाजपा के कार्यकाल में दिया गया था।

वहीं 2003 में राजस्थान में एक बार ऐसी स्थिति बनी कि राज्य के तीन सबसे बड़े पदों पर महिलाएं आसीन थीं। उस समय राज्यपाल प्रतिभा पाटील थीं, मुख्यमंत्री पद पर वसुंधरा राजे और विधानसभा अध्यक्ष पद पर सुमित्रा सिंह थीं। राजस्थान विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए भले ही महिलाओं को कम मौका मिला हो, लेकिन मतदान करने में उन्होंने पुरुषों के मुकाबले अधिक दिलचस्पी दिखाई है। चुनाव में पुरुषों का जहां मतदान प्रतिशत 73.80 प्रतिशत रहा,[5] वहीं 74.66 महिलाओं ने वोटिंग की है। इस बार पिछले चुनाव के मुकाबले एक प्रतिशत कम मतदान हुआ है। राज्य निर्वाचन विभाग ने मतदान के अंतिम आंकड़े जारी कर दिए। प्रदेश में सबसे अधिक मतदान पिछड़े माने जाने वाले सरहदी जिले जैसलमेर में हुआ है तो सबसे कम पाली जिले में हुआ। राजस्थान की प्रथम विधानसभा के आम चुनाव में महिलाओं का प्रतिनिधित्व जीरो था। यानी एक भी महिला पहले चुनाव में निर्वाचित होकर विधानसभा नहीं पहुंची। अब 14वीं विधानसभा में महिलाओं की हिस्सेदारी शून्य से साढ़े तेरह प्रतिशत तक बढ़ गई है। यह देशभर की विधानसभाओं में सबसे ज्यादा प्रतिनिधित्व है।

1) तब पंडित नेहरू ने यह कहा था

राजस्थान की महिलाओं में राजनीतिक जागृति की कमी पर टिप्पणी करते हुए 31 मार्च 1954 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पं.जवाहरलाल नेहरू ने अफसोस जताते हुए कहा था- कल मैं आपकी विधानसभा देखने गया था। मुझे यह देखकर बड़ी हैरत हुई कि 160 सदस्यों वाले सदन में महिला विधायक सिर्फ एक है। राजस्थान महिलाओं के मामले में बहुत पिछड़ा हुआ है। हमें उन्हें आगे लागा होगा।

वास्तव में पं. नेहरू की यह पीड़ा सही थी, जो उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री जयनारायण व्यास के आवास पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की एक बैठक में व्यक्त की थी। उस समय एकमात्र महिला विधायक यशोदा देवी थीं, जो समाजवादी पार्टी के टिकट पर बांसवाड़ा क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित हुई थीं।

इसके दो माह बाद यानी जून 1954 में आमेर-बी विधानसभा क्षेत्र का उपचुनाव हुआ। यहां से आम चुनाव में निर्दलीय विधायक संग्राम सिंह ने इस्तीफा दे दिया था।

इस उपचुनाव में दलीय प्रत्याशी बनाने के लिए कांग्रेस के रामकरण जोशी गुट ने भूदेव शर्मा का नाम भिजवाया, जो आम चुनाव में हार गए थे। इसके विपरीत चौधरी कुंभाराम गुट ने कमला बेनीवाल के नाम की सिफारिश की जो उस समय जयपुर के किसी सरकारी स्कूल में इतिहास की अध्यापिका थीं। इस नाम के पीछे चौधरी की सोच थी कि दो महीने पहले ही पं. नेहरू ने महिलाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी।

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

इसलिए उन्हें कमला का नाम उपयुक्त लगा। वजह ये भी थी कि राजस्थान के एक बड़े स्वतंत्रता सेनानी चौधरी नेतराम सिंह की बेटी हैं और वनस्थली विद्यापीठ की पहली स्नातक छात्रा हैं। जहां तक उनके सरकारी सेवा में होने का प्रश्न है, वहां से त्यागपत्र दिलवा लेंगे। [7]

कांग्रेस ने चौधरी कुंभाराम का प्रस्ताव मानकर कमला बेनीवाल को प्रत्याशी बनाया। वे उपचुनाव जीत गईं। बाद में 6 नवंबर 1954 में कांग्रेस विधायक दल के नेता के लिए जयनारायण व्यास और मोहनलाल सुखाड़िया के बीच हुए चुनाव में कुंभाराम की सुखाड़िया के पक्ष में अहम भूमिका रही। उनके सुझाव पर कमला बेनीवाल को सुखाड़िया मंत्रिमंडल में उपमंत्री के रूप में शामिल कर लिया गया।

आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है। तमाम बड़े सियासी नेता और राजनीतिक दल महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई दे रहे हैं, महिलाओं के उत्थान और उन्हें राजनीतिक भागीदारी बढ़ाने के बड़े-बड़े दावे करते हैं लेकिन बावजूद इसके आज भी राजनीति में महिलाओं की भागीदारी ज्यादा नहीं है। हालांकि पंचायत और निकाय चुनाव में भले ही महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था लागू कर दी गई हो लेकिन विधानसभा और लोकसभा महिलाओं की भागीदारी कम ही है। इसका सबसे बड़ा जीता जागता उदाहरण राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है जहां पर महिला विधायकों की भागीदारी 13 फ़ीसदी है। इसके अलावा बड़ी बात ये हैं कि राजस्थान से राज्यसभा में भी एक भी महिला की भागीदारी नहीं है। राज्यसभा की 10 सीटों में से एक पर भी महिला सांसद नहीं है। हालांकि लोकसभा में जरुर 25 में से तीन महिला लोकसभा सांसद हैं

बड़ी बात यह कि प्रदेश की सबसे बड़ी पंचायत राजस्थान विधानसभा में 200 विधायकों में से केवल 27 महिला विधायक ही हैं। इस लिहाज से राजस्थान विधानसभा में महिला विधायकों का प्रतिनिधित्व केवल 13 फ़ीसदी है इनमें सत्तारूढ़ कांग्रेस से 15, भाजपा से 10, रालोपा से एक और एक महिला निर्दलीय विधायक है। ऐसे में सवाल ही उठता है कि राजनीतिक दलों की ओर से महिलाओं को राजनीति में भागीदारी देने के बड़े-बड़े वादे और दावे तो किए जाते हैं लेकिन उन पर अमल नहीं होता है।

भारत में स्वतंत्रता के बाद पहली केंद्र सरकार (जवाहरलाल नेहरू की सरकार में) के पास 20 कैबिनेट मंत्रालयों में केवल एक महिला (राजकुमारी अमृत कौर) थी, जिन्हें स्वास्थ्य मंत्रालय का प्रभार दिया गया था। एक भी महिला को लाल बहादुर शास्त्री की सरकार में जगह नहीं दी गई। यहां तक कि इंदिरा गांधी की 5 वीं, 6 वीं, 9 वीं कैबिनेट में एक भी महिला केंद्रीय मंत्री नहीं थी। राजीव गांधी के मंत्रिमंडल में केवल एक महिला (मोहसिना किदवई) को शामिल किया गया था।[8]
मोदी सरकार में महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ है। 2014 में, मोदी सरकार में कुल नौ महिला सांसदों को कैबिनेट और राज्य मंत्री बनाया गया था। 16 वीं लोकसभा में 61 महिला उम्मीदवार जीती हैं। यह अब तक का उच्चतम है। 543 सदस्यीय लोकसभा में महिला उम्मीदवारों की संख्या 2009 में 58 से अधिक है। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च के अनुसार, "यह देश के इतिहास में लोकसभा में पहुंचने वाली महिलाओं की सबसे अधिक संख्या है। 2009 में, 58 महिलाएं पहुंची। लोकसभा। "प्रमुख महिला उम्मीदवार जो संसद का मार्ग प्रशस्त करने में कामयाब रहीं उनमें कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी (रायबरेली), भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की वरिष्ठ नेता सुषमा स्वराज (विदिशा), उमा भारती (झाँसी, मेनका गाँधी (पीलीभीत), पूनम महाजन (शामिल हैं) मुंबई नॉर्थ सेंट्रल), किरण खेर (चंडीगढ़), राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी) की सुप्रिया सुले (बारामती), समाजवादी पार्टी (सपा) के नेता दिपाल यादव (कन्नौज)। गौरतलब है कि सोनिया, सुषमा, उमा, मेनका, सुप्रिया, डिंपल को पहले संसद जाने का मौका मिला है, जबकि पूनम, किरण के लिए यह पहला कार्यकाल होगा। इस चुनाव में कई प्रमुख महिला उम्मीदवार हार गईं, जिनमें कांग्रेस नेता अंबिका सोनी (अंबाला), कृष्णा तीरथ (उत्तर पश्चिम दिल्ली), गिरिजा व्यास (चित्तौड़गढ़), लोकसभा अध्यक्ष मीरा कुमार (सासाराम), बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी (सरन), उनकी बेटी मीसा भारती (पाटलिपुत्र)। पश्चिम बंगाल से सबसे अधिक 13 महिला सांसद संसद के निचले सदन में पहुंचने में कामयाब रहीं, जबकि उत्तर प्रदेश की 11 महिलाओं को इस बार संसद जाने का मौका मिला। 2009 में, 58 महिलाएं संसद में पहुंचीं, जबकि 2004 में 45 और 1999 में 49 महिलाएं जीतीं। लोकसभा में सबसे कम महिलाएं 1957 में देखी गईं, जब उनकी संख्या केवल 22 थी।

क्या वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी नहीं है जैसी बीस साल पहले थी? इस सवाल पर अक्सर डेटा का आकलन किया जाता है। बड़े पैमाने पर, महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में आजादी के बाद उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले, लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। जिसकी आज जरूरत भी है। अन्य क्षेत्रों

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

में, महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले। घर की सीमा से लेकर शिक्षा, बैंकिंग, कॉरपोरेट क्षेत्र में उन्होंने अपनी योग्यता को पुरुषों के रूप में साबित किया है और अपने लिए सम्मानजनक स्थान बनाया है। चुनावों में समान भागीदारी की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन इसके लिए सामाजिक सोच, प्रणालीगत बदलाव,[9] सामाजिक विकास और सबसे अधिक शिक्षित और स्वस्थ वातावरण आवश्यक है। साथ ही उच्च सिद्धांतों को शामिल करना बहुत महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर पर भी, कुछ पहल करनी होगी जिसमें शिक्षित महिलाएं, भले ही वे ग्रामीण इलाकों की हों, उन्हें आगे आने का मौका मिलता है। ऐसे प्रयास जिसमें स्वस्थ स्तर पर महिलाओं की भागीदारी संभव हो सकेगी। सरकार ने ऐसी कई योजनाओं को मूर्त रूप दिया है। जिसमें महिलाओं के कल्याण और उनके विकास को भी प्रमुख मुद्दों में शामिल किया गया है। 73 वें और 74 वें संशोधन के तहत महिलाओं को पंचायतों में सीटों और नगर निकायों के स्थानीय निकायों में आरक्षण प्रदान किया गया है। ताकि राजनीति में उनकी भागीदारी को एक मजबूत आधार प्रदान किया जा सके। कई कृत्यों में सुधार और सभी भेदभाव को समाप्त करके समानता को प्रमुखता दी गई है।

परिणाम

राजस्थान की राजनीति में साल 2022 बहुत अहम रहा. एक तरफ कुछ नेताओं का भविष्य तय हुआ, तो दूसरी तरफ कुछ विधायकों ने अपने बयानों से खूब सुर्खियां बटोरीं. राजस्थान में कुल 200 विधानसभा सीटें हैं, जिसमें से 27 पर महिला विधायक हैं.

वर्ष 2022 में कांग्रेस की महिला विधायक दिव्या मदेरणा (Divya Maderna) चर्चा में रहीं. वहीं, बीजेपी के लिए शोभा रानी कुशवाहा (Shobha Rani Kushwaha) बड़ी मुसीबत बनीं. राजस्थान सरकार में मंत्री जाहिदा खान (Zahida Khan) भी खूब चर्चा में रहीं. आइये जानते हैं आखिर इन्होंने ऐसा क्या बोला है, जो इनकी पार्टी के लिए महंगा पड़ गया था.

दिव्या मदेरणा ने अपनी सरकार को ही 'घेरा' दिव्या मदेरणा (Divya Maderna) जोधपुर की ओसियां विधानसभा सीट (Osian Assembly Seat) से कांग्रेस की विधायक हैं. दिव्या ने हमेशा मुखर होकर अपनी हर बात रखी है, लेकिन 25 सितंबर को जयपुर में जो सियासी ड्रामा हुआ उसके बाद से लगातार दिव्या वह मीडिया में बनी रहीं.

दिव्या मदेरणा ने खुलकर कुछ नेताओं के खिलाफ बोला. 'भारत जोड़ो यात्रा' के दौरान राहुल गांधी के साथ फोटो की वजह से भी दिव्या मदेरणा ने सुर्खियां बटोरीं. दिव्या सोशल मीडिया पर खूब चर्चा में रहती हैं. मुख्यमंत्री हों या फिर कोई और मंत्री, सभी को दिव्या ने समय-समय पर मुद्दों को लेकर खूब घेरा है. कई बार तो सरकार पर सवाल उठा दिया और कई बार मुख्यमंत्री से सीधे सवाल ही कर दिया.[10]

शोभा रानी कुशवाहा अकेली बीजेपी विधायक भारत संभाग में धौलपुर से बस शोभा रानी कुशवाहा (Shobha Rani Kushwaha) ही अकेले बीजेपी से चुनाव जीत पाई थीं. लेकिन उन्होंने भी बीजेपी से बगावत कर दी. वो चर्चा में तब आईं, जब राजस्थान में राज्यसभा के लिए मतदान देना था और उन्होंने क्रॉस वोट कर दिया था. क्रॉस वोटिंग से चर्चा में आने के बाद उन्हें बीजेपी प्रदेश नेतृत्व और केंद्रीय अनुशासन समिति ने 'कारण बताओ नोटिस' दिया था.

इसके बाद शोभा रानी कुशवाहा को पार्टी से निष्कासित कर दिया गया. इससे पहले शोभारानी ने मीडिया में बयान देकर बीजेपी के राष्ट्रीय स्तर के कुछ नेताओं पर पंचायत चुनाव में अपनी ही पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर आरोप लगाया था. लेकिन शोभारानी अभी भी विधायक हैं.

जाहिदा खान क्यों आई थीं चर्चा में जाहिदा खान (Zahida Khan) राज्य मंत्री हैं और राजनीति में काफी चर्चा में बनी रहती हैं. जाहिदा खान भरतपुर के कामां से कांग्रेस की विधायक हैं. पिछले दिनों भरतपुर के पहाड़ी क्षेत्र में मंडी समिति के चुनाव में जाहिदा खान वहां गईं. किसी ने उन्हें फूलों की माला पहनाकर स्वागत किया, लेकिन जाहिदा खान ने कहा था कि 'फूलन सूं तो काम नहीं चलेगा'. आज हमको काम करके जांगा. इतने में ही स्वागत करने वाले सदस्य ने जाहिदा खान के मन की बात परख ली और फिर 500-500 रुपए के नोट की एक करीब 51 हजार रुपए की माला पहनाई. इसके बाद से जाहिदा खान हमेशा चर्चा में बनी हुई हैं.

कुल 27 महिला विधायक राजस्थान विधानसभा में इस बार कुल 27 महिला विधायक हैं, जिनमें से बीजेपी के पास 10 की संख्या है. कांग्रेस के पास कुल 15 महिला विधायक हैं. रमीला खड़िया ने बांसवाड़ा की कुशलगढ़ सीट से निर्दलीय चुनाव जीता है. वहीं, नागौर

| ISSN: 2395-7639 | www.ijmrsetm.com | Impact Factor: 7.580| A Monthly Double-Blind Peer Reviewed Journal |

| Volume 10, Issue 8, August 2023 |

की मेड़ता विधानसभा सीट से इंद्रा देवी ने आरएलटीपी से चुनाव जीता है. इस साल राजस्थान की राजनीति भले ही खूब चर्चा में रहीं, लेकिन इनमें से बस कुछ ही विधायक हैं जो मीडिया में चर्चा में बनी रहीं.

निष्कर्ष

भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका का अध्ययन राजनीतिक दृष्टिकोण से किया गया है। इस शोध पत्र में राजनीति में महिलाओं की भागीदारी, वर्तमान स्थिति, समस्याओं और महिलाओं के राजनीतिक भविष्य का अध्ययन किया गया है। वर्तमान राजनीति में महिलाओं की भागीदारी वैसी ही स्थिति नहीं है जैसी बीस साल पहले थी। दुनिया के इतिहास में राजनीति एक दुर्जेय कार्य रही है। राजनीति ने लोगों का शोषण किया है, धर्म की रक्षा और लोगों के जीवन और संपत्ति की रक्षा के नाम पर खून बहाया है। इसलिए राजनीति न केवल आम आदमियों की बल्कि उन पुरुषों की भी अखाड़ा रही है जो कठोर और क्रूर व्यवहार करते हैं। राजनीति पुरुषों की शारीरिक शक्ति और इससे उत्पन्न होने वाले अहंकार के साथ सक्रिय रही है। इसलिए, राजनीति में तुलनात्मक रूप से नरम स्वभाव की महिलाओं की भागीदारी पूरी दुनिया में कम रही है।[8] राजनीति में महिलाओं की भागीदारी न केवल भारत में बल्कि पूरे विश्व के इतिहास में एक अपवाद रही है। स्वतंत्रता के बाद से महिलाओं की राजनीति में भागीदारी के प्रतिशत में उत्तरोत्तर सुधार हुआ है। सबसे पहले, लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्यों और निर्देशक सिद्धांतों में प्रस्तावित किया गया है। संविधान ने न केवल महिलाओं को समानता का दर्जा दिया है, बल्कि महिलाओं के पक्ष में सकारात्मक भेदभाव के उपाय करने के लिए राज्य को सशक्त बनाया है। जिसकी आज जरूरत भी है। अन्य क्षेत्रों में, महिलाओं को अपने प्रभुत्व को स्थापित करते हुए एक ऊर्जावान और ठोस तरीके से चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। राजनीति के नए आयाम बनाए जा रहे हैं जिसमें महिलाओं को समान रूप से प्रोत्साहित किया जा रहा है, भले ही वह पंचायती स्तर पर ही क्यों न हो। गाँव के सरपंच ने कई पंचायत स्तर के चुनावों में महिला उम्मीदवारों को जीता और उन्नति के नए द्वार खोले।[9,10]

प्रतिक्रिया दें संदर्भ

1. Verma, Sudhir (1997). "Women's Struggle for Political Space-ß Jaipur: Rawat Publications. P, 2 , 5 , 25 .
2. Reynolds, Andrew (1999). "Women in the Legislatures and Effectives of the World Knocking at the Highest Glass Ceiling-ß World Politics, Vol. 51 , PP. 547 - 72 , 75 .
3. शर्मा, प्रज्ञा (2011). " वुमन इन इंडियन सोसाइटी. जयपुरः पॉइंटर पब्लिशर्स, पेज - 162, 165.
4. चोपड़ा, पी. ए. एन. पुरी, बी. पी. एन., दास एम. एन. (2005). " भारत का सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक इतिहास "। दिल्लीः मैकमिलन इंडिया लिमिटेड पृष्ठ - 259, 265.
5. शर्मा, गोपीनाथ (2008). " राजस्थान का सांस्कृतिक इतिहास। " " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी। पृष्ठ - 119 , 120
6. शर्मा, कालूराम। (2004). " उन्नीसवीं सदी के राजस्थान का सामाजिक और आर्थिक जीवन। " " जयपुरः राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, पृष्ठ - 125 , 129
7. जैन, हुकुमचंद और माली, नारायण। (2011). " राजस्थान का इतिहास और संस्कृतिः विश्वकोश "। " जयपुरः जैन प्रकाशन मंदिर। पृष्ठ - 548, 555
8. अंसारी, एम ए (2010) " महिला और मानव अधिकार जयपुरः ज्योति प्रकाशन।
9. कैथवास, सावित्री (2009) " ग्रामीण पंचायती राज के विशेष संदर्भः अनुसूचित जाति और जनजाति की महिलाओं के राजनीतिक सशक्तीकरण की प्रक्रिया में आने वाली बाधाएं: नए पंचायती राज के विशेष संदर्भ में। 25, पृष्ठ - 30, 32, 43
10. शर्मा, प्रज्ञा (2011) " महिला विकास और सशक्तिकरण "। " जयपुरः अविष्कार पब्लिशर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स

Impact Factor: 7.580

INTERNATIONAL JOURNAL
OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH
IN SCIENCE, ENGINEERING, TECHNOLOGY AND MANAGEMENT

+91 99405 72462 +91 63819 07438 ijmrsetm@gmail.com